वाह री सरकार! कहीं एक नहीं तो कहीं 3-3 कर दिए तैनात

एनआईटी हमीरपुर के हेल्थ सेंटर में तीन फार्मासिस्ट दे रहे सेवाएं

रविंद्र चंदेल। हमीरपुर

इसे सरकार के सिस्टम की खामी माने या मनमर्जी का कानून कि कहीं तो एक फार्मासिस्ट नहीं है और कहीं तीन-तीन के डेरे हैं। जी हां ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला केंद्रीय बजट से चलने वाले एनआईटी हमीरपुर के हेल्थ सेंटर में सामने आया है, जहां तीन-तीन फार्मासिस्ट नियुक्त हैं। हालांकि हेल्थ सेंटर में दवाई देने का काम आउटसोर्स की गई केमिस्ट शॉप के जिम्मे है, जो कि 15 फीसदी छपे हुए मूल्य से कम मूल्य पर दवाई बेचने के लिए अनुबंधित की गई है। लेकिन जब केमिस्ट शॉप अनुबंधित मूल्य पर दवाइयां दे रही है तो ऐसे में तीन-तीन फार्मासिस्टों की क्या जरूरत आन पड़ी है। सरकारी हेल्थ मशीनरी की माने तो अस्पतालों में फार्मासिस्ट का काम मरीजों को दवाइयां देना, स्टाक प्रबंधन को देखना, दवाइयों का हिसाब रखना होता है। इसलिए फार्मासिस्ट रखे गए होते हैं, लेकिन जिस हेल्थ सेंटर में दवाइयों का प्रबंध ही केमिस्ट शॉप के हवाले है, उस छोटे से हेल्थ सेंटर में फार्मासिस्टों की फौज की जरूरत क्या है। एनआईटी सूत्रों की माने तो इन तीन फार्मासिस्टों का 15 लाख के करीब सालाना खर्चा संस्थान कर रहा है। एनआईटी के हेल्थ सेंटर में 1 स्थायी डॉक्टर के अलावा 4 पार्ट टाइम डॉक्टर अनुबंध के आधार पर तैनात है, जो सिर्फ तीन घंटे के लिए आते हैं, जिनको 500 रुपये के हिसाब से संस्थान भुगतान करता है। 2 स्टाफ नर्सिज आउटसोर्स पर तैनात की गई हैं, 3 फार्मासिस्ट हैं, जिनमें से एक रेगुलर है व 2 आउटसोर्स पर हैं। एक चपरासी नियुक्त किया गया है। इस तरह एक दर्जन लोगों का स्टाफ एनआईटी के हेल्थ सेंटर में तैनात किया गया है। जब एनआईटी के सत्र चले होते हैं, तब 80 से 90 मरीजों की ओपीडी रोजना दर्ज की जाती है, जबकि अवकाश के दिनों में तो कभी 4-5 या कभी 1 भी मरीज नहीं आता।

◆ बड़े बजट की बड़ी व्यवस्था पर बड़ा सवाल

हेल्थ सेंटर में नहीं दी जाती जेनेरिक दवाइयां

भले ही एनआईटी हमीरपुर का तामझाम केंद्रीय बजट से चलता हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेनेरिक दवाइयों की मुहिम को यहां सरेआम धता दिखाया जाता है। एनआईटी का हेल्थ सेंटर केवल स्टेंडड कंपनियों की दवाइयां ही मरीजों को देता है।

मामला मेरे कार्यकाल से पहले का है। बिना काम के हेल्थ सैंटर में तीन फार्मासिस्ट क्यों तैनात हैं, इस पर जांच के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है।

-प्रो. विनोद यादव, डायरेक्टर
एनआईटी, हमीरपुर

यहां दो प्रिंसिपलों के बीच पिस रहा स्टाफ

एक देता है आदेश तो दूसरा कर देता है रद

राजीव शर्मा। बड़सर

बड़सर उपमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैलीजजरी में प्रदेश सरकार द्वारा एक साथ दो प्रिंसिपलों को तैनात कर दिया है। इसके चलते शिक्षा संस्थान में तैनात स्टाफ में भी असमजंस की स्थिति पैदा हो गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा करीब एक महीना पहले स्कूल में प्रिंसिपल की तैनाती की थी, जबकि स्कूल में पहले ही प्रिंसिपल मौजूद था। जिन्हें अभी स्कूल में तैनात हुए को लगभग दो वर्ष का समय भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने पहले से तैनात प्रधानाचार्य सुशील धीमान का तबादला जिला शिमला के लिए कर दिया और उनके स्थान पर सुखदेव कालिया को रैलीजजरी में तैनात कर दिया, लेकिन प्रधानाचार्य सुशील धीमान ने कोर्ट से स्टे ले लिया। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा एक स्थान पर ही दो प्रिंसिपलों की तैनाती करके बच्चों व स्कूल में कार्यरत स्टाफ को समस्या पैदा हो गई है। एक प्रिंसिपल द्वारा जहां आदेश पारित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे द्वारा उन्हें रद कर दिया जा रहा है। ऐसे में स्टाफ में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किसके आदेशों को माने और किसके नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले लंबे समय से स्कूल में महौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में क्या निर्णय लेती है जिससे स्कूल स्टाफ व बच्चों की समस्या का समाधान हो सके।

◆ रैलीजजरी स्कूल में एक पद पर दो की तैनाती से माहौल तनावपूर्ण

गोदाम से गायब लकड़ी पर सीआईडी ने शुरू की जांच

टीम ने स्टोरकीपरों के बयान किए कलमबद्ध

◆ सीआईडी की दबिश से दियोटसिद्ध में मचा हड़कंप

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। हमीरपुर

हिमाचल दस्तक फॉलोअप

मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्ध के गोदामों से गायब हुई लाखों की इमारती लकड़ी के खुलासे के बाद मंदिर कार्यालयों में हड़कंप की स्थिति है। उधर, सीआईडी विभाग ने मामले की तह तक जाने के लिए मंगलवार को मंदिर कार्यालय दियोटसिद्ध में दबिश दी। सीआईडी अधिकारियों ने तमाम रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही स्टोर से संबंधित कर्मचारियों से घंटों अकेले कमरे में पूछताछ की, लेकिन सीआईडी के हाथ अभी तक कोई बड़ा सबूत नहीं लगा है। मंदिर के स्टॉक रजिस्टर में काटे गए तूहनी की लकड़ी का कोई हवाला दर्ज नहीं है। सीआईडी की जांच के बाद मंदिर के भरोसेमंद सूत्रों ने खुलासा किया कि स्टोरकीपरों की मौजूदगी में मंदिर अधिकारी की कोठी के सामने बनी दुकानों में रखी लकड़ी के स्टॉक के फिजिकल वेरिफिकेशन सीआईडी अधिकारियों ने की है। हालांकि इस कार्रवाई से मंदिर अधिकारी नदारद रहे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि स्टोर में अब तीन से चार फुट के करीब 14-15 मोछे ही शेष बचे हैं, जोकि सिर्फ अब बालन के ही काम आ सकते हैं। सीआईडी द्वारा कलमबद्ध हुए बयानों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि तत्कालीन मंदिर अधिकारी की हिदायत पर लकड़ी का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। एक बयान में यह भी कहा गया है कि तूहनी के पेड़ की परिधि का डाया चार से पांच फुट ही था, जबकि अभी भी जिन लोगों के पास पुराने मंदिर भवन के चित्र मौजूद हैं, उन्हें देखने से अनजान भी बता सकता है कि वर्षों पुराना तूहनी का डाया 10 से 12 फीट परिधि का रहा होगा, जिन कामगारों ने इस तूहनी की इमारती लकड़ी को स्टोर में रखा था, उनकी माने तो 6 से 7 ट्रॉलियों में भरकर इस लकड़ी को स्टोर में पहुंचाया गया था, जिसके कुल नग 37 से 40 के बीच थे, जिनमें से 12 से 15 नग 2 से 3 फुट चौड़े व 9 से 12 फुट तक लंबे थे।

वन विभाग की भूमि से काटा गया है पेड़

कर्मचारियों के बयानों से स्पष्ट है कि अधिकारियों की हिदायत पर इमारती लकड़ी का ब्योरा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह समझा जा रहा है, जहां से यह वर्षों पुराना बेशकीमती पेड़ काटा गया है, वह भूमि मंदिर ट्रस्ट की है ही नहीं। वन भूमि से काटे गए इस पेड़ को लेकर कोई पचड़ा न हो इसी मंशा से इस इमारती लकड़ी का ब्योरा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इस तरह अब इस मामले में एक नई अपराधिक कड़ी जुड़ गई है कि सरकारी अधिकारियों ने ही मंदिर परिसर में अवैध कटान की वारदात को अंजाम दिया था।

जर्जर हुए भवन की चीजों की नीलामी 14 अगस्त को

भोरंज। खंड चिकित्सा अधिकारी भोरंज ललित कालिया ने बताया कि नागरिक चिकित्सालय भोरंज में आवासीय भवन टाइप 4 धरातल व पहली मंजिल 1 नए टाइप 2 धरातल व पहली मंजिल 2 न और टाइप 1 सिंगल स्टोरी दो भवन, जो कि जर्जर हो चुके हैं तथा इन्हें असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन भवनों में लगी सामग्री पत्थर, लकड़ी व स्लेट इत्यादि की नीलामी 14 अगस्त को 11 बजे खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भोरंज में रखी गई है। नीलामी की शर्तों को नीलामी से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में 10 बजे से 5 बजे तक कार्यालय में देखा जा सकता है।

शादियों में निजी स्कूल बसों की बुकिंग पर होगी कार्रवाई

हिमाचल दस्तक। सुजानपुर

उपमंडल सुजानपुर के जो भी निजी स्कूल अपनी बसों का इस्तेमाल विवाह-शादियों में करते हैं, अब यह कार्य उन्हें महंगा पड़ सकता है। इस संबंध में गाड़ी जस होने के साथ-साथ इसका रूट भी रद किया जा सकता है। लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के ऊपर विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है। इस संबंध में सर्वप्रथम निर्देश जारी करके सभी स्कूल प्रबंधकों को इस तरह के कार्य न करने को कहा गया है और इस विषय में जल्द ही एक विशेष बैठक का आयोजन करके दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें कि क्षेत्र के कुछ निजी स्कूल चंद पैसों के लालच में अपनी बसों को बारात के साथ-साथ अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, चंद जिनकी लगातार शिकायतें विभाग के पास पहुंच रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन अपनी बसों में बुकिंग आदि लेने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लगातार हादसे होने का डर रहता है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित विभाग से इस तरह के कार्य करने वाले निजी स्कूल प्रबंधकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और यह भी कहा है कि जो भी स्कूल प्रबंधन इस तरह का कार्य करते हैं उनके स्कूल रूट रद किए जाएं। उधर, इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया निजी स्कूल प्रबंधन से इस संबंध में बैठक करके निर्देश जारी किए जाएंगे और इस तरह का कोई भी कार्य स्कूल करता पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

◆ शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने लिया फैसला

◆ जल्द ही निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक करेगा विभाग

अफसरों से ली निर्माण कार्यों की रिपोर्ट

सुक्खू ने नादौन अस्पताल के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश

हिमाचल दस्तक। नादौन

विधानसभा क्षेत्र के चार दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बैठक ली। सेरा विश्राम गृह में बुलाई बैठक में पीडब्ल्यूडी के हमीरपुर डिवीजन के अधिशाषी अभियंता विवेक शर्मा व एसडीओ राजकुमार धीमान शामिल हुए। सुक्खू ने अधिकारियों के साथ अब तक के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट ली।

उन्होंने मिनी सचिवालय नादौन व नागरिक अस्पताल के काम की प्रगति भी जानी। नादौन अस्पताल के निर्माण कार्य की धीमी गति पर विधायक नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने अधिकारियों को जल्दी काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मिनी सचिवालय में लिफ्ट जल्दी लगाने को भी कहा। सुक्खू ने अधिशाषी अभियंता व एसडीओ को जंदली गुजरां-थाइं मोड़, निचला वन-पनियाला, तरेटी-मण, कुहाल से बड़ी बां और अम्लैहड़ू से बडेहतर सड़क की वर्तमान स्थिति सुधारने के साथ ही जल्दी पक्का करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे बरसात के बाद उपमंडल की सड़कों का निरीक्षण कर उनकी मरम्मत करें, ताकि लोगों व वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो। सुक्खू ने कहा कि नादौन अस्पताल के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों से बातचीत हुई है। बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चेकअप कराने के लिए कहीं और न जाना पड़े। इसलिए डॉक्टरों की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। मिनी सचिवालय का काम तेज गति से चल रहा है और इसके पूरा होने पर सभी विभाग एक छत के नीचे आ जाएंगे। यह प्रदेश का पहला वातानुकूलित मिनी सचिवालय होगा। सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

सेरा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेते कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू।

◆ मिनी सचिवालय में लिफ्ट के काम को भी जल्द पूरा करने के आदेश

धार बगेड़ा में बनाया जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट

◆ एसडीएम को मिली एनजीटी के आदेश की कॉपी

हिमाचल दस्तक। सुजानपुर

सुजानपुर शहर का कूड़ा-कचरा धार बगेड़ा में फेंका जाएगा। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया है। फैसला सार्वजनिक होते ही प्रतिलिपि उपमंडल अधिकारी सुजानपुर के पास पहुंच गई है। इसमें नगर परिषद सुजानपुर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण धार बगेहड़ा में करने के लिए कहा गया है। एक माह के भीतर प्लांट बनाने संबंधी भूमि स्थानांतरण कार्य पूरा होना चाहिए और उसी दौरान प्लांट को बनाने का कार्य शुरू होना चाहिए।

अगर जारी किए गए आदेशों की अवहेलना होती है या कोई सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश जारी होते ही सुजानपुर शहर की अब तक की सबसे बड़ी समस्या का हल निकल गया है। सुजानपुर प्रशासन ने करीब चार स्थानों संबंधित प्लांट बनाने के लिए स्थान चयनित किए थे और इस संबंध में अपना पक्ष एनजीटी कार्यालय में रखा था। एनजीटी कार्यालय द्वारा इसके ऊपर 11 जुलाई को पहली बैठक दिल्ली में रखी गई थी। इसमें सुजानपुर प्रशासन और पंचायत प्रधान ने पक्ष रखा था। लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके लिए दो अगस्त को दोबारा विशेष बैठक दिल्ली में में रखी गई। इस बैठक में इस पूरे मसले पर एनजीटी ने अपना फैसला सुना दिया है।

अभी हमीरपुर भेजा जाता है कचरा

सुजानपुर नगर परिषद अब तक कूड़ा-कर्कट प्रतिदिन हमीरपुर लेकर पहुंच रही है। क्योंकि जिस स्थान पर नगर परिषद पहले कूड़ा फेंकती थी, उस स्थान पर एनजीटी ने नगर परिषद सुजानपुर को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस स्थान पर कूड़ा नहीं फेंका जाएगा। इसके लिए आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण करवाएं। लेकिन जैसे ही नगर परिषद ने प्लांट को बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की तो नजदीकी पंचायतों के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। सारा मामला एनजीटी कार्यालय में चला गया।

एनजीटी ने सुजानपुर नगर परिषद को धार बगेहड़ा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

- शिवदेव सिंह
एसडीएम, सुजानपुर

बड़सर। किसानों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा।

मोदी ने रखा किसानों का ख्याल: बलदेव

फसलों का समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाकर दी बड़ी राहत

हिमाचल दस्तक। बड़सर

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों को फसलों का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलेगा। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक निर्णय से किसानों को अपनी ऊपज पूरा लाभ होगा। बड़सर में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करके किसानों को लाभ पहुंचाया है। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इसे लागू करने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर को लोकसभा में सचेतक बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है।

जल्द मिलेगी उपमंडी की सौगात

कृषि उपसमिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि बड़सर के किसानों के लिए जल्द ही उपमंडी की सौगात दी जाएगी। बड़सर भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने उपमंडी की मांग रखी गई।

अड़ंगा — ठेकेदार की मनमानी के आगे लोक निर्माण विभाग लाचार

सड़कों पर पेवर टाइल लगाने का काम लटका

राज कुमार। मैहरे

बड़सर की सड़कों पर पेवर टाइल लगाने के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कार्य अधर में लटका हुआ है। इसे ठेकेदार की मनमानी समझे या फिर लोक निर्माण विभाग की लाचारी कि संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग की कुछ एक सड़कों पर ठेकेदार द्वारा पेवर टाइल स्थापित करने का कार्य तो शुरू कर दिया, लेकिन इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया है। कायदे के अनुसार विभाग द्वारा किसी भी कार्य को आर्वंटित करते समय गुणवत्ता व समय अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही ठेकेदार को कार्य सौंपा जाता है। यदि ठेकेदार द्वारा कार्य समय रहते पूरा नहीं किया जाए तो ऐसे में उक्त ठेकेदार को कार्य में देरी करने के लिए पेनल्टी तक प्रावधान होता है। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू न करना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौर हो कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इलाके की सड़कों पर कुछ एक स्थान ऐसे थे जहां पर सड़क की टारिंग या पैचवर्क करने के कुछ दिन बाद ही सड़कों की हालत खराब हो जाती थी, जिससे लोक निर्माण विभाग को हर साल लाखों रुपये की चपत लग जाती थी। इसी के मद्देनजर स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जो कि उस दौरान सीपीएस थे, ने बड़सर की ईएसआई सड़कों पर पेवर टाइल लगवाने के लिए प्रदेश सरकार से करीब दस करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करवाई थी। सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद सभी दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई और पेवर टाइल लगवाने का कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया गया। लेकिन, ठेकेदारों द्वारा कुछ एक स्थानों पर कार्य करने के बाद विभाग द्वारा पास की गई पेवर टाइल के स्थान किसी अन्य कंपनी की टाइल लगाना शुरू कर दी। इसी के मद्देनजर विभाग ने ठेकेदारों को कार्य आर्वंटित होने से पूर्व पास की गई कंपनी की ही टाइल लगाने के आदेश जारी किए, लेकिन ठेकेदार विभागीय आदेशों को दरकिनार कर मनमर्जी की टाइल लगाने के लिए अडियल रवैया अपनाए हुए है। यही कारण है कि पिछले करीब नौ महीने से ठेकेदार द्वारा पेवर टाइल लगाने के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया है। अब यदि ठेकेदार द्वारा यदि विभाग द्वारा पास की गई कंपनी की टाइल को नहीं लगाना था तो ऐसे में कार्य आर्वंटित होने से पूर्व ही मना कर देते, ताकि विभाग कम से कम किसी अन्य ठेकेदार को कार्य आर्वंटित कर बड़सर की सड़कों पर पेवर टाइल तो स्थापित कर देता।

सड़कों पर पेवर टाइल लगोन के रुके कार्य को ठेकेदार को शुरू करने के कई बारे आदेश जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके ठेकेदार कार्य को करने में आनाकानी कर रहा है। विभाग ने ठेकेदार पर नियमानुसार कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

-अनिल कुमार,
सहायक अभियंता
लोक निर्माण विभाग, बड़सर

INOX WIND LIMITED

Regd. Off.: Plot No.1, Khasra No. 264 to 267, Industrial Area, Village-Basal, Distt. Una-174303, Himachal Pradesh
CIN: L31901HP2009PLC031083 | Tel./ Fax: 01975-272001 | E-mail: investors.iwl@inoxwind.com | Website: www.inoxwind.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2018

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30-06-2018 (Unaudited)	Quarter Ended 31-03-2018 (Audited)	Quarter Ended 30-06-2017 (Unaudited)	Year ended 31-03-2018 (Audited)
1.	Total Income from operations	43,045	20,341	10,599	47,984
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	1,812	(8,348)	(5,814)	(28,048)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,812	(8,348)	(5,814)	(28,048)
4.	Net Profit/Loss for the period after tax (after exceptional items)	1,037	(5,566)	(3,902)	(18,761)
5.	Total Comprehensive Income/(Expense) for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	1,024	(5,517)	(3,863)	(18,530)
6.	Reserves excluding revaluation reserves	-	-	-	178,236
7.	Paid-up equity share capital (face value Rs. 10 per share)	22,192	22,192	22,192	22,192
8.	Earnings per share (face value of Rs.10/- each) (not annualized)				
	a) Basic (Rs.)	0.47	(2.51)	(1.76)	(8.45)
	b) Diluted (Rs.)	0.47	(2.51)	(1.76)	(8.45)

Notes:

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on 7th August, 2018. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above results for the quarter ended 30th June, 2018.
2. The above results are an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.inoxwind.com).
3. Information on Standalone Financial Results : (Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30-06-2018 (Unaudited)	Quarter Ended 31-03-2018 (Audited)	Quarter Ended 30-06-2017 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2018 (Audited)
1.	Total income from operations	38,904	8,097	4,452	21,243
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	2,195	(6,271)	(4,671)	(23,963)
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	1,411	(4,023)	(3,088)	(15,717)

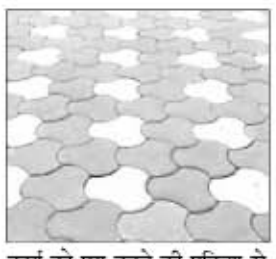

On behalf of the Board of Directors
For Inox Wind Limited

Place: Noida
Date : 7th August, 2018

Devansh Jain
Whole-time Director